



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 856) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2016

सं० 22 नि० सि० (अभि०)–प००–21–04/2010/2189—श्री उदय शंकर प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-2, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के विरुद्ध मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज के अन्तर्गत एकरारनामा सं० 25F₂/2000–01 एवं 29F₂/2000–01 के तहत श्री किशोर कुमार जायसवाल, संवेदक के द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों के विरुद्ध विभागीय पत्रांक 353 दिनांक 03.03.01 के आलोक में 40% राशि का भुगतान किया गया। शेष लंबित राशि के भुगतान हेतु समय—समय पर विभाग से आवंटन की माँग की गयी एवं 8 वर्षों के बाद लंबित भुगतान हेतु दायित्व समिति का गठन किया गया, जिसके श्री उदय शंकर प्रसाद, अध्यक्ष/सदस्य थे, परन्तु दायित्व समिति की बैठक में कलर्भर्ट के गुणवत्ता की जाँच नहीं किया गया, का झूटा प्रतिवेदन अपने उच्चाधिकारियों एवं माननीय उच्च न्यायालय को देते हुए दावे को अमान्य कर दिया, साथ ही श्री प्रसाद द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किये बिना ही उक्त तिथि तक संपादित कार्यों का 40% का ही भुगतान हेतु प्रतिवेदन देने एवं संवेदक द्वारा कराये गये कार्यों के लंबित भुगतान को नहीं कर संवेदक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से हानि पहुँचाने और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्तव्य का पालन नहीं करने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प 320 दिनांक 16.03.11 द्वारा बिहार पेशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने उपरोक्त आरोप के प्रथम अंश दायित्व समिति की विभिन्न बैठकों में मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के द्वारा समर्पित कार्यों के पूर्ण प्रतिवेदन एवं आवंटन की माँग किये जाने के पश्चात भी संवेदक के कार्यों को अपूर्ण माने जाने एवं पक्का कार्यों की गुणवत्ता की जाँच नहीं किये जाने के कारण संवेदक के दावे को दायित्व समिति के द्वारा अमान्य करने का निर्णय लेने के लिए दोषी पाया गया तथा आरोप का द्वितीय अंश कि संवेदक को करीब 8 वर्षों की लम्बी अवधि तक उनके द्वारा कराये गये कार्यों के लंबित भुगतान को नहीं कर संवेदक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से हानि पहुँचायी गयी, का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

श्री प्रसाद के विरुद्ध उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन देते हुए विभागीय पत्रांक 2119 दिनांक 17.09.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरुद्ध दायित्व समिति के सदस्य के रूप में दायित्व समिति के द्वारा संवेदक के दावे को अमान्य करने के निर्णय लेने के आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री उदय शंकर प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-2, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को “10% पेंशन की कटौती पाँच वर्षों तक” का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया।

उपर्युक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1691 दिनांक 06.09.16 द्वारा सहमति प्राप्त है। उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री उदय शंकर प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-2, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:-

“10% पेंशन की कटौती पाँच वर्षों तक”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 856-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>